



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361]

नई दिल्ली; सोमवार, जुलाई 3, 2000/आषाढ़ 12, 1922

No. 361]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 3, 2000/ASADHA 12, 1922

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2000

सा.का.नि. 582 (अ).—केंद्रीय सरकार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 30) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति नियम, 2000 है।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपक्षित न हो—

(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ;

(ख) “सदस्य” से अभिप्रेत है उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्य ;

(ग) “सचिव” से अभिप्रेत है उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव ;

(घ) अन्य सभी शब्द और पद जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं के वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

3. धारा 3क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं— (1) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति में नौ सदस्यों से अधिक नहीं होंगे ।

(2) निम्नलिखित व्यक्ति उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के पदेन सदस्य होंगे :-

- (i) भारत का महा न्यायाधीश ;
- (ii) विधि कार्य विभाग, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का अपर सचिव या उसका नाम निर्देशिती ;
- (iii) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का अपर सचिव या उसका नाम निर्देशिती ; और
- (iv) भारत के उच्चतम न्यायालय का महा रजिस्ट्रार ।

(3) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, अन्य सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके पास उक्त नियमों के उपनियम (4) में विहित अर्हताएं और अनुभव हैं ।

(4) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह :-

(क) विधि के क्षेत्र में कोई विख्यात व्यक्ति न हो ; या

(ख) कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति न हो जो विशेष रूप से विधिक सेवा स्कीमों के कार्यान्वयन में हितबद्ध है ;

(ग) कोई विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता न हो जो समाज के कमजोर वर्गों जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, बालक, ग्रामीण और शहरी श्रमिक भी हैं, के उन्नयन में लगा हुआ है ।

4. धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव के लिए अनुभव और अर्हताएं— कोई व्यक्ति सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह :-

(क) उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री का, संयुक्त रजिस्ट्रार से पंक्ति में अनिम्न अधिकारी न हो ; या

(ख) केंद्रीय सरकार में निदेशक की पंक्ति का कोई अधिकारी न हो जो विधि में डिग्री रखता हो ।

5. धारा 3क की उपधारा (5) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या— उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति में सचिवीय सहायता देने और दिन प्रतिदिन के कृत्यों के करने के लिए इन नियमों की अनुसूची में वर्णित या जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं अधिकारी और अन्य कर्मचारी होंगे ।।

6. धारा 3क की उपधारा (6) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और उन्हें संदेय वेतन और भत्ते— (1) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी इन नियमों की अनुसूची में प्रत्येक पद के सामने उपदर्शित या केंद्रीय सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारियों के बराबर वेतनमान में वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे ।

(2) सेवानिवृत्ति की आयु, वेतन और भत्ते, फायदों, हकदारियों और अनुशासनिक विषयों जैसे सभी मामलों में उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और कर्मचारी, केंद्रीय सरकार के उन नियमों से शासित होंगे जो समतुल्य पदों के धारक व्यक्तियों को लागू हैं ।

(3) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली अन्य सुविधाओं और फायदों के हकदार होंगे ।

स्पष्टीकरण— इन नियमों में आने वाले “फायदों”, “भत्तों”, “हकदारियों”, “सुविधाओं” शब्दों में, केंद्रीय सरकार के समतुल्य पदों के धारक कर्मचारियों को उपलब्ध उपदान, भविष्य निधि, आवास, चिकित्सा लाभ, पेंशन, समूह बीमा की हकदारी और अन्य सभी फायदे सम्मिलित समझे जाएंगे।

7. यदि मामला उच्चतम न्यायालय में हो तो धारा 12 के खंड (ज) के अधीन विधिक सेवाओं के लिए हकदार होने के लिए किसी व्यक्ति की अधिकतम वार्षिक आय सीमा — ऐसा व्यक्ति जिसकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 50,000 रुपए (पचास हजार रुपए) से अधिक न हो, उक्त अधिनियम की धारा 12 के खंड (ज) के अधीन विधिक सेवाओं का हकदार होगा।

8. धारा 19 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा संगठित लोक अदालत के अन्य व्यक्तियों के लिए अनुभव और अर्हताएं — कोई व्यक्ति लोक अदालत में सम्मिलित किए जाने के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह—

(क) विधि व्यवसाय का सदस्य न हो ; या

(ख) ऐसा ख्याति प्राप्त व्यक्ति न हो जो विधिक सेवा स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में विशेष रूप से हितबद्ध हो ; या

(ग) ऐसा विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता न हो जो समाज के कमजोर वर्गों, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, बालक, ग्रामीण और शहरी श्रमिक भी हैं, के उत्थान में लगा हुआ हो।

[फा.सं. ए. 60011(14)/99-प्रशा. III(एल.ए.)(नाल्सा)]

आर. एल. कोली, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2000

G.S.R. 582(E).— In exercise of the powers conferred by section 27 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the Central Government in consultation with Chief Justice of India, hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Supreme Court Legal Services Committee Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. **Definitions.** - In these rules unless the context otherwise requires —

(a) “Act” means the Legal Services Authorities Act, 1987;

(b) "Member" means the Members of the Supreme Court Legal Services

Committee nominated under clause (b) of sub-section (2) of section

3A of the Act;

(c) "Secretary" means the Secretary of the Supreme Court Legal Services

Committee appointed under sub-section (3) of section 3A of the Act;

(d) all other words and expressions used in these rules but not defined

shall have the same meaning as assigned to them in the Act .

3. The number, experience and qualifications of Members of the Supreme Court Legal Services Committee under clause(b) of sub-section (2) of section 3A. -

(1) The Supreme Court Legal Services Committee shall consist of not more than nine Members.

(2) The following shall be the ex-officio Members of the Supreme Court Legal Services Committee:-

- (i) Attorney General of India;
- (ii) Additional Secretary in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Government of India or his nominee;
- (iii) Additional Secretary in the Department of Expenditure of the Ministry of Finance, Government of India or his nominee; and
- (iv) Registrar General of the Supreme Court of India.

(3) The Chief Justice of India may nominate other Members from amongst those possessing the qualification and experience prescribed in sub-rule (4) of the rules.

(4) A person shall not be qualified for nomination as a Member unless he is:-

- (a) an eminent person in the field of law; or
- (b) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes; or
- (c) an eminent social worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the society including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, women, children, rural and urban labour.

4. The experience and qualifications of Secretary of the Supreme Court Legal Services Committee under sub-section (3) of section 3A. - A person shall not be qualified for appointment as Secretary unless he is:-

- (a) an officer of the Supreme Court Registry not below the rank of Joint Registrar; or
- (b) an officer of the rank of Director in the Central Government and possessing a degree in Law.

5. The number of officers and other employees of the Supreme Court Legal Services Committee under sub-section (3) of section 3A. - The Supreme Court Legal Services Committee shall have such number of officers and other employees for rendering secretarial assistance and for its day-to-day functions as are set out in the Schedule to these rules or as may be notified by the Central Government from time to time.

6. The conditions of service and the salary and allowances payable to the officers and employees of the Supreme Court Legal Services Committee under

sub-section (6) of section 3A- (1) The officers and other employees of the Supreme Court Legal Services Committee shall be entitled to draw pay and allowances in the scale of pay indicated against each post in the Schedule to these rules or at par with the Central Government employees holding equivalent posts.

(2) In all matters like age of retirement, pay and allowances, benefits and entitlements and disciplinary matters, the officers and employees of the Supreme Court Legal Services Committee shall be governed by the Central Government rules as are applicable to persons holding equivalent posts.

(3) The officers and other employees of the Supreme Court Legal Services Committee shall be entitled to such other facilities and benefits as may be notified by the Central Government from time to time.

Explanation- The words “benefits”, “allowances”, “entitlements”, “facilities” occurring in these rules shall be deemed to include, the entitlement to gratuity, provident fund, housing, medical benefits, pension, group insurance, and all other benefits as are available to employees of the Central Government holding equivalent posts.

7. The upper limit of annual income of a person entitling him to legal services under clause (h) of section 12, if the case is before the Supreme Court- A person whose annual income from all sources does not exceed Rs.50,000 (Rupees fifty thousand) per annum shall be entitled to legal services under clause (h) of section 12 of the Act.

8. The experience and qualifications of other persons of the Lok Adalats organised by the Supreme Court Legal Services Committee specified in sub-

section (3) of section 19. - A person shall not be qualified to be included in the Lok Adalat unless he is,-

- (a) a member of the legal profession; or
- (b) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes and Programmes;
or
- (c) an eminent social worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the society, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, women, children, rural and urban labour.

[F. No. A 60011(14)/99-Admn. III(LA)(NALSA)]

R. L. KOLI, Jt. Secy. and Legal Adviser

